

पीठाधीश्वर स्वामी माधवाचार्य महाराज का गुफा मंदिर में हुआ आगमन



संत हिरदाराम नगर। श्री रामानंद सम्प्रदाय के टीला द्वारा गाद्याचार्य मंगल पीठाधीश्वर स्वामी माधवाचार्य महाराज डाकोर, मुंबई राज्य अतिथि म.प्र.शासन का शुक्रवार को श्री रामानन्द आश्रम गुफा मन्दिर धाम में आगमन हुआ। मंदिर परिसर में ही स्थित धाम के नवीन कार्यालय का उद्घाटन महाराज के द्वारा किया गया। इस अवसर पर गुफा मंदिर के महंत रामप्रवेशदास महाराज सहित कई उपस्थित थे। पंडित लेखराज शर्मा ने बताया कि माधवाचार्य महाराज भोपाल में धार्मिक यज्ञ आदि कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इस अवसर पर वह गुफा मंदिर धाम में 29 मई तक रहेंगे।

नवनिध विद्यालय की छात्राओं को परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने पर प्रशस्ति पत्र मिले

संत हिरदाराम नगर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आयोजित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में इस वर्ष भाग लेने व अपने विचार साझा करने के लिए नवनिध हासोमल लखानी पब्लिक स्कूल की छात्राओं में दीक्षा छुगानी, दीक्षा सतानी, योगिता आस्वानी, नैना आनंदानी, खुशबू बच्छानी, अनुषा अग्रवाल, वंशिका पर्यानी, हेमा सतवानी, प्राची चेलानी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुए। इसी तारकम्य में भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई निबंध प्रतियोगिताओं में मध्यप्रदेश से चुने गए सर्वश्रेष्ठ 50 विजेताओं में से नवनिध विद्यालय की छात्रा स्नेहा कुशलानी, सुहानी बसंतानी को राज्य स्तरीय विजेता के रूप में चुना गया है। निबंध प्रतियोगिता में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु इन छात्राओं को पुरस्कार स्वरूप 4 हजार की राशि व प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं।

मुकुल सेन जिला अध्यक्ष बने

भोपाल। मध्य प्रदेश सेन समाज संयुक्त कल्याण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हीरालाल श्रीवास ने सूरज नगर एयरपोर्ट रोड भोपाल के मुकुल सेन को मध्य प्रदेश युवा प्रकोष्ठ सेन समाज संगठन भोपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस नियुक्ति पर प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य मुकेश सेन कुलदीप सेन करणी सेना के उपाध्यक्ष सुदर्शन सिसोदिया गोवर्धन विश्वकर्मा संतोष सेन प्रेम सेन ईश्वर सेन सतीश सेन परसराम सेन बदाम सेन महेश सेन सीताराम सेन समाज बंधुओं ने मुकुल सेन को बधाई दी और सेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष हीरालाल श्रीवास का आभार व्यक्त किया



मेपलावर पब्लिक स्कूल की छात्रा जिले में प्रथम



भोपाल। मध्य प्रदेश हायर सेकेंडरी बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षा परिणामों में मेपलावर पब्लिक स्कूल शानदार उपलब्धि हासिल की है मे पलावर स्कूल के छात्र आरती मेवाड़ा ने भोपाल जिला में प्रथम स्थान हासिल किया मेपलावर एजुकेशन सोसायटी की अध्यक्ष सोफिया सिद्दीकी ने बताया कि दसवीं का परीक्षा परिणाम 89.4 प्रतिशत और 12वीं का परीक्षा परिणाम 88 प्रतिशत रहा। 1986 में मेपलावर स्कूल की शुरुआत की गई है। ग्राम खजूरी कला में में पलावर स्कूल की एक और ब्रांच खोली गई है। सिद्दीकी ने बताया कि उनकी कोशिश थी कि ग्रामीण परिवेश के बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम से शिक्षा मिले और उसी का परिणाम है कि ग्रामीण पपरिवेश से ही एक छात्र ने इस बार भोपाल जिला में मेरिट लिस्ट में प्रथम हासिल हासिल किया है। मेपलावर पब्लिक स्कूल में इस समय 14 सौ से अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं

4 जून को होगा सबधाणी प्रतिभा सम्मान समारोह



भोपाल। विगत दिवस आए बारहवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में भोपाल के कई छात्र-छात्राओं ने बेहतरीन अंक हासिल किए हैं, इन प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं का सम्मान 4 जून को सबधाणी कोचिंग द्वारा सबधाणी कोचिंग, द्वितीय तल, 114, जून-2, सिटी हॉस्पिटल के बगल में, एम पी नगर, भोपाल में प्रातः 10 से 2 बजे के बीच शिक्षा जगत की कई बड़ी हस्तियों की उपस्थिति में किया जाएगा। समारोह के अध्यक्ष एवं सबधाणी कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आनंद सबधाणी ने बताया कि इस वर्ष 2023 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड, आइएससी या सीएआई बोर्ड में 60: या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राएं अपना नाम, प्रतिशत, स्कूल का नाम, फोटोग्राफ और मार्कशीट 1 जून तक सबधाणी कोचिंग के

व्हाट्सएप नंबर 8839066328 पर भेज सकते हैं। सभी को रविवार 4 जून को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। ज्ञात है कि सबधाणी कोचिंग इंस्टीट्यूट, भोपाल द्वारा प्रतिवर्ष इस प्रकार का सम्मान समारोह 85: से अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए किया जाता रहा है परंतु सबधाणी की नयी सोच के अनुसार 85, 90 या 95 प्रतिशत अंक अर्जित करने वालों का सम्मान तो पूरी दुनिया करती है, परंतु सबधाणी कोचिंग इस बार ऐसे विद्यार्थियों का भी सम्मान करेगा जो कोशिश तो 90 प्रतिशत अंकों की करते हैं लेकिन प्रतिस्पर्धा के कारण 60 प्रतिशत अंक ही अर्जित कर पाते हैं। ऐसे विद्यार्थी उचित सम्मान एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर भविष्य में टॉपर्स की श्रेणी में भी जा सकते हैं और भविष्य में देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। संवाददाता से चर्चा में सबधाणी ने कहा कि चांद पर पहला कदम किसने रखा है यह सब जानते हैं, परंतु कितने लोगों ने प्रयास किया यह शायद कोई नहीं जानता, परंतु उम्र जानेंगे। सबधाणी के इस ऐतिहासिक प्रयास की कई अभिभावकों, सामाजिक संस्थाओं, स्कूल प्रबंधन द्वारा सराहना भी की जा रही है।

संस्कार स्कूल में रंगारंग कार्यक्रम के साथ समर कैम्प का हुआ समापन

बच्चों ने नृत्य, खेलकूद, संगीत सीखा और भरपूर आनंद लिया

संत हिरदाराम नगर। संस्कार स्कूल में ग्रीष्मकालीन अवकाश के अवसर पर आयोजित समर कैम्प का समापन शुक्रवार को रंगारंग कार्यक्रम के साथ किया गया। इस ग्रीष्मावकाश में नाना प्रकार की गतिविधियों का संचालन किया गया था। जिनमें नृत्य, खेलकूद, संगीत, चित्रकला, अंग्रेजी सुलेख व अंग्रेजी भाषा को बोलने की शिक्षा प्रमुख थी। कार्यक्रम का शुभारम्भ समाजसेवी घनश्याम थारानी, संस्था के सचिव बसंत चेलानी, उपाध्यक्ष सुरेश राजपाल, सदस्य नारायणदास लालवानी, रिटा. कर्नल नारायण पारवानी, विष्णु गेहानी द्वारा किया गया। संस्था के सचिव बसंत चेलानी ने आए हुए अतिथियों का परिचय दिया एवं अभिभावकों से कहा कि आज हमारे संस्कार स्कूल के समर कैम्प समापन हो रहा है समर कैम्प की शुरुआत में हमने आश्वासन दिया था कि जो कुछ भी बच्चे समर कैम्प में सीखेंगे उसे आप आकर देखना कि आपने अपने बच्चों को शिविर में भेजकर जो भरोसा जताया है उस हिसाब से बच्चों ने इस समर कैम्प में बहुत कुछ सीखा तथा इस समर कैम्प का भरपूर आनन्द लिया। घनश्याम थारानी ने बच्चों को सम्बोधित करते हुए कहा कि जो सूर्योदय देखता है उसके भाग्य का उद्य भी जल्दी होता है। कार्यक्रम में उपस्थित रिटा. कर्नल श्री नारायण पारवानी ने कहा कि बच्चे समर वेकेशन को वेस्ट करते हैं लेकिन इन बच्चों ने छुट्टियों का सदुपयोग करके कुछ सीखा है उस हुनर को आगे बढ़ाए एवं उसकी प्रैक्टिस करते रहें जो लेटेस्ट है उसे आपको अपडेट रखना है।



संस्कार स्कूल के एमपी बोर्ड में अत्तल रहे विद्यार्थियों का हुआ सम्मान

संत हिरदाराम नगर। संस्कार पब्लिक स्कूल का कक्षा दसवीं का परीक्षा परिणाम 93 प्रतिशत एवं कक्षा बारहवीं का परीक्षा परिणाम 90 प्रतिशत रहा। संत नगर के बाकी विद्यालयों की अपेक्षा संस्कार विद्यालय का रिजल्ट अधिक उत्कृष्ट रहा। इस अवसर पर विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। विद्यालय में हाई स्कूल में विद्यालय स्तर पर आकृति शर्मा ने 95.60 प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया एवं प्रियांशी राठीर 94.80 प्रतिशत अंक के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया एवं समीक्षा नागर

94.40 प्रतिशत अंकों के साथ तृतीय स्थान पर रही। हायर सेकण्डरी में वाणिज्य संकाय में कशिश सबरवाल 89 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रही, हितेश नागर 88.20 प्रतिशत अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान पर रहा तथा लीना सोभनानी 86 प्रतिशत तृतीय स्थान, विज्ञान संकाय में अदिति कहार एवं जिया श्रीचन्दानी 92.20 प्रतिशत अंक लेकर प्रथम स्थान पर रही, उदय पाटीदार 92 प्रतिशत अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान पर रहा एवं इशिका देवड़ा 90.40 प्रतिशत अंकों के साथ तृतीय स्थान पर रही।



पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पौधारोपण करना अत्यंत आवश्यक : विष्णु गेहानी



संत हिरदाराम नगर। सुधार सभा द्वारा संचालित साधु वासवानी स्कूल में शिक्षाविद् विष्णु गेहानी ने पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पौधारोपण किया। शिक्षा जगत में लंबे समय से सेवा करने और 88 वर्ष की उम्र में भी वह आज भी बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। विष्णु गेहानी ने गरीब बच्चों को गणवेश, पशु-पक्षियों के लिए दाना-पानी, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पौधारोपण एवं पौधों का वितरण तथा डस्टबिन, झाड़ू देकर स्वच्छता की शपथ दिलवाई। इस अवसर पर शिक्षाविद् विष्णु गेहानी ने कहा कि मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरा बाकी बचा हुआ जीवन इन बाल-गोपालों की सेवा में व्यतीत हो और अमले जन्म में भी मैं शिक्षक बनकर इसी तरह बच्चों की सेवा करता रहूँ। उन्होंने कहा कि सभी यह संकल्प करें कि बच्चों का भविष्य अच्छा बनाने के साथ-साथ उन्हें अच्छा इंसान भी बनाएँ साथ ही पौधे लगाकर पर्यावरण को शुद्ध रखने भी अपना योगदान देंगे। इस अवसर पर पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष साबुल रीझवानी, बोरवन क्लब के अध्यक्ष जगदीश आसवानी भी उपस्थित थे।

ईश्वर नगर में बनेंगी सड़कें और नालियां, लगेंगे पेविंग ब्लॉक

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

महापौर मालती राय ने ईश्वर नगर में विभिन्न विकास कार्यों हेतु विधिवत भूमिपूजन किया। नगर निगम द्वारा वार्ड क्र. 50 के अंतर्गत ईश्वर नगर क्षेत्र में लगभग 25 लाख रुपये की लागत से सड़क, नाली एवं पेविंग ब्लॉक लगाने का कार्य किया जा रहा है। ईश्वर

नगर में शुक्रवार को आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम में महापौर मालती राय ने उपस्थितजन को संबोधित करते हुए कहा कि हम शहर के सभी क्षेत्रों में विकास एवं जनसुविधा संबंधी कार्य निरंतर करा रहे हैं और इसी क्रम में आज वार्ड क्र. 50 सड़क, नाली, पेविंग ब्लॉक सहित अन्य विकास कार्यों के लिए भूमिपूजन किया है और इन

कार्यों के पूर्ण होने पर शीघ्र ही आवागमन में सुविधा के साथ ही पानी की निकासी आदि की सुविधाएं और अधिक बेहतर ढंग से सुनिश्चित होंगी। भूमिपूजन अवसर पर स्थानीय पार्षद एवं महापौर परिषद की सदस्या सुषमा बाबोसा के अलावा वरिष्ठ समाज सेविका सीमा सिंह, पूर्व पार्षद करतात सिंह तोमर सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद थे।



भोपाल। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर आयुक्त नगर निगम के मार्गदर्शन में भोपाल नगर निगम की कर्वावाई 10 टन 3 क्विंटल अमानक प्लास्टिक जस की और 50 हजार का स्पांट फाइन लगाया नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के थोक सप्लायर, होलसेलर पर औचक निरीक्षण की कार्यवाही की गई जिसमें अलग-अलग जोन के, 148 और प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी विजेंद्र गुप्ता ने संयुक्त टीम बनाकर सिंगल यूज प्लास्टिक जब्ती की बड़ी कार्यवाही की गई। चार घंटे तक चली इस कार्यवाही कर घोड़ा नक्कास अमृत प्लास्टिक की दुकान पर 276 बोरी पांच डंपर अमानक प्लास्टिक की जसी की गई एवं 50 हजार रु स्पांट फाइन किया गया, सिंगल यूज प्लास्टिक जब्ती और फाइन की कार्यवाही निरंतर की जाती रहेगी। एक अलग कार्यवाही में प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी राकेश शर्मा ने विजय मार्केट में 65 किलो अमानक प्लास्टिक जब्त कर 2500 रुपये का फाइन किया गया। नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा अमानक प्लास्टिक पर सतत रूप से कार्यवाही की जाती रहेगी।

मांगों को लेकर सहरिया समाज ने कलेक्टर सौंपा झापन



भोपाल । अखिल भारतीय सेहरिया समाज महासभा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष फूल सिंह सेमरिया के नेतृत्व में भोपाल संभाग के 5 जिले से आए हुए समाज के लोगों को साथ रैली के रूप में भोपाल कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जी के नाम का झापन भोपाल कलेक्ट्रेट कार्यालय में संतोष भिंड मुरैना, के जैसा सीधा लाभ प्रदान कराए जावे एवं विशेष पिछड़ी जनजाति में सम्मिलित की जावे उक्त जिलों मे सहरिया समाज को नोकरियों में सीधी भर्ती एवं शासन

जनजाति को विशेष पिछड़ी आदिम जनजाति में शामिल कर ग्वालियर एवं चंबल संभाग के सहरिया समाज की तरह सीधा लाभ दिया जाए। भोपाल संभाग में सहरिया समाज निवासरत है जोकि बहुत अति पिछड़ी हुई जनजाति है। इस कारण भोपाल संभाग को ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिलों ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, भिंड मुरैना, के जैसा सीधा लाभ प्रदान कराए जावे एवं विशेष पिछड़ी जनजाति में सम्मिलित की जावे उक्त जिलों मे सहरिया समाज को नोकरियों में सीधी भर्ती एवं शासन

की कई प्रकार की विशेष योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया जाता है उसी तरह भोपाल संभाग के जिलों को ला प्रधान किया जाए। इस अवसर पर भोपाल संभाग के 5 जिलों से भारी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। झापन सौंपने के अवसर पर मुख्य रूप से हुजूर ब्लॉक अध्यक्ष दीपक चौहान सहरिया सरपंच, गोवर्धन सरिया अध्यक्ष जिला भोपाल, रामदयाल सहरिया, दीपक चौहान, रामभरोसे सहरिया, भारत सिंह चौहान प्रदेश उपाध्यक्ष, सतीश सांवरे प्रदेश महामंत्री आदि उपस्थित थे।

नहीं कर सकेंगे इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन का कारोबार, कलेक्टर ने किया आदेश

भोपाल । कलेक्टर ने भोपाल में हो रहे नशे के कारोबार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के आदेश किए हैं। यह आदेश हुक्का लाउंज के साथ ही अन्य माध्यमों से अवैध इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन का कारोबार करने वालों के लिए सख्त कदम उठाया है। जिसे युवाओं को नशे से होने वाली गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके। जिले के विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट सहित अन्य नशीले पदार्थों का संग्रहण एवं विक्रय किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलिवरी सिस्टम उपयोगकर्ता विभिन्न रसायनों के संपर्क में आते हैं जैसे नाइट्रोसामाइन, बेंजोन, इथिलोन ऑक्साइड, और एक्रोला माइड जो स्वास्थ्य प्रभावों के साथ के कैंसर एवं तंत्रिका तंत्र को भी क्षति पहुंचा सकते हैं। ये उत्पाद बड़े पैमाने पर विशेष रूप से बच्चों, किशोरावस्था, गर्भवती महिलाओं और प्रजनन आयु की महिलाओं के लिए एक बड़ा स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भण्डारण और विज्ञापन) का प्रतिषेध कानून 2019 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उसके बाद भी शहर में अवैध रूप से नशे के कारोबार किया जा रहा है। कलेक्टर ने जनता और शहर की हितों में निर्णय लेते हुए थारा 144 पालन करते हुए प्रबंध किया जाता है। इस प्रतिबंध के बाद भी कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है तो उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

लाड़ली बहना योजना में 10 जून से सभी महिलाओं के खाते में डाली जाएगी राशि

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बकतरा में सीताराम महायज्ञ में शामिल हुए, एक करोड़ की लागत से सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा की



सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मानव जीवन में परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनियों द्वारा तीन अलग-अलग मार्ग- ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग बताए गए हैं। इन तीनों मार्ग पर चल कर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संत ज्ञान मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करते हैं, मीराबाई और हनुमान की तरह भक्ति मार्ग से भी भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। साथ ही हम अपने जीवन में सही रास्ते पर चल कर कर्म करते हुए भी कर्म मार्ग से भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि हम सभी को कर्म मार्ग पर चलने की कोशिश करना चाहिए। मुख्यमंत्री चौहान बुधनी विवाखण्ड के ग्राम बकतरा में सीताराम महायज्ञ में शामिल हुए और संतों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने बकतरा में एक करोड़ रूपए की लागत से सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि भगवान ने जो काम अपने लिए निश्चित कर दिया है, उसको मेहनत और ईमानदारी से करेंगे तो भगवान को प्राप्त करना आसान होगा। यदि

किसान पूरी मेहनत और लगन से खेती कर फसल उगाए, डॉक्टर निस्वार्थ भाव से मरीजों का इलाज करें और शिक्षक ईमानदारी से बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे

मुख्यमंत्री ने कूनों में चीतों की मृत्यु के संबंध में ली जानकारी

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में प्रदेश में चीतों के बसाने संबंधी गतिविधियों की समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री को वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने चीतों को बसाने, उनको क्रॉसिंग रखने की अवधि और उनकी देख-रेख से जुड़े विभिन्न पहलु पर जानकारी दी गई। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य-प्राणी) द्वारा कूनों स्थलों पर स्वागत मंच से मंत्री सारंग का आभार व्यक्त किया और राईट गार्डन में बड़ी संख्या में रहवासी उपस्थित रहे।

मई को चीता शावकों की हुई मृत्यु के संभावित कारण पोषण में कमी तथा अत्यंत गर्मी का मौसम प्रतीत होता है। चौथे शावक को रेस्क्यू कर वन्य-प्राणी चिकित्सकों की निगरानी में इलाज किया जा रहा है। शावक के स्वास्थ्य में सुधार दिख रहा है। मृत शावकों का वजन अत्यंत कम 1.6 कि.ग्रा. था, जबकि मानकों के अनुसार इस आयु के शावकों का वजन लगभग 3 कि.ग्रा. होना चाहिये। कुल छह चीतों को खुले जंगल में छोड़ा गया है, जिनकी दिन-रात मॉनिटरिंग की जा रही है। आगामी दिनों में 3 और चीतों को खुले जंगल में छोड़े जाने की योजना है।

गांधीसागर अभयारण्य में भी आवश्यक तैयारी प्रारंभ हो चुकी है, जो नवम्बर तक पूरी होने की संभावना है। इसी तरह नौरादेही अभयारण्य में भी तैयारी प्रारंभ की जानी है। बैठक में निर्देश दिये गये कि नौरादेही तथा गांधीसागर अभयारण्य में इन तैयारियों के लिए टाइम लाइन निर्धारित कर इसे नवगठित प्रोजेक्ट चीता स्टीयरिंग कमेटी से अनुमोदन करवायें। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, प्रधान मुख्य वन संरक्षक रमेश कुमार गुप्ता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य-प्राणी) जे.एस. चौहान और अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य-प्राणी) शुभ रंजन सेन उपस्थित थे।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने सड़क सहित कई विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने शुक्रवार को नरेला विधानसभा अंतर्गत वार्ड-75 एवं 76 में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया। मंत्री सारंग ने कहा कि नरेला में निरन्तर विकास से मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि के साथ जन-सामान्य की समस्याओं का निराकरण भी हो रहा है। क्षेत्र के विकास कार्य निर्धारित समय पर हो सकें, इसके लिये क्षेत्र की मैपिंग कर कैलेंडर बनाया गया है, इससे निश्चित समयावधि में सभी निर्माण कार्य पूर्ण किये जा रहे हैं। विकास कार्यों की सीमागत के लिये क्षेत्र के नागरिकों ने मंत्री सारंग का आभार व्यक्त करने रोड-शो किया। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि, नागरिक कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में रहवासी उपस्थित रहे।



मंत्री सारंग ने नरेला विधानसभा में किये गये विकास कार्यों और क्षेत्र की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2008 के पहले नरेला विधानसभा में मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। वर्तमान में नरेला विधानसभा में सबसे ज्यादा विकास के कार्य हुए हैं, जो निरंतर जारी हैं। उन्होंने कहा कि नरेला को पेयजल संकट से मुक्ति दिलाते

थीम पार्क सहित विभिन्न विकास कार्यों की सीमागत रहवासियों को मिली है। भूमि-पूजन के दौरान अचानक बूढ़ाबांदी संग बारिश शुरू हो गयी। इस दौरान भी रहवासियों का उत्साह कम नहीं हुआ। विभिन्न स्थानों पर स्वागत मंच से मंत्री सारंग का आभार व्यक्त किया और ढोल-ढमाकों और आतिशबाजी के बीच पुष्पवर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया गया।

राज्यपाल से मिले विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजातीय छात्र-छात्राएं

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने युवाओं का आह्वान किया है कि ज्ञान की नई रोशनी के साथ समाज के विकास के संवाहक बनें। देश-समाज के विकास के भाव के साथ कार्य में ही जीवन की सार्थकता है। राज्यपाल पटेल राजभवन में संवेदना संस्थान के तत्वावधान में राजभवन भ्रमण के लिए आए विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजातीय छात्र-छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल के प्रमुख सचिव डी. पी. आहूजा उपस्थित थे। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान को सबसे शक्तिशाली हथियार बताया था। जीवन की सभी तरह की चुनौतियों का सामना शिक्षा से ही हो सकता है। वर्तमान पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि शिक्षा किसी धर्म, वर्ग के लिए सीमित नहीं रही है। मेहनत, लगन, मजबूत इच्छा शक्ति से जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने गुजरात की नेत्र बाधित बालिका का उल्लेख किया।

कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान को सफल बनाने में जुट जाएं: विष्णुदत्त शर्मा

प्रदेश अध्यक्ष ने खजूरारो लोकसभा क्षेत्र की बैठक को किया सम्बोधित

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की केंद्र सरकार के सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने पर 30 मई से 30 जून तक खजूरारो लोकसभा क्षेत्र में वृहद जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचावेंगे। अभियान में व्यापक जनसंपर्क, लाभार्थी संपर्क, समाज के विभिन्न वर्गों से संपर्क, प्रबुद्धजन एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जायेगा। पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता इस अभियान को सफल बनाने में पूरी ताकत से जुट जाएं। यह बात पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजूरारो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने शनिवार को प्रदेश कार्यालय में खजूरारो लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक को सम्बोधित करते हुए कही। प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में प्रदेश शासन के



मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह वचुंअली जुड़े। प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि खजूरारो लोकसभा में स्थित विकास के प्रमुख स्थल जो विकास तीर्थ हैं, ऐसे स्थलों पर स्थानीय विकास से लाभान्वित लोगों के साथ चर्चा की जाएगी। विशाल जनसभा को केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय पदाधिकारी सम्बोधित करेंगे। खजूरारो में 2 जून को पत्रकार-वार्ता का आयोजन कर केन्द्र सरकार की उपलब्धियों को बताया जायेगा। लोकसभा क्षेत्र में सोशल मीडिया के प्रमुख इफ्लुएंसर के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि संपर्क से

समर्थन वृहद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। व्यापारिक केंद्र पर प्रमुख व्यापारियों के साथ व्यापारी सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 21 जून को योग दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही आमजन भी कार्यक्रम में शामिल होंगे एवं केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 23 जून को डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उद्घोषण को व्यापक रूप में सुनने का आह्वान किया।

87 महिला उद्यमियों को मिला 4.60 लाख का 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान

भोपाल। मध्यप्रदेश महिला वित्त विकास निगम की अध्यक्ष श्रीमती अमिता चपरा द्वारा गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना में 87 महिला उद्यमियों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान के रूप में 4 लाख 60 हजार रूपये अंतरित किये गये। श्रीमती अमिता ने बताया कि अगस्त-2022 में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन कर मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया था। इसमें प्रदेश में ग्रामीण/शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों के लिये 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इस योजना प्रदेश में महिला उद्यमिता को विकसित करने के साथ तकनीकी कौशल आधारित उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाते हुए राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना है।

निर्माणाधीन निगम मुख्यालय भवन का किया निरीक्षण

स्ट्रक्चर और स्लैब का काम जून अंत तक पूरा करें: चौधरी

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

निगम आयुक्त के.वी.एस. चौधरी ने निर्माणाधीन निगम मुख्यालय भवन का निरीक्षण किया और भवन के भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल एवं ऑडिटोरियम के प्रचलित एवं प्रस्तावित कार्यों के संबंध में अधिकारियों, इंजीनियर, कंसलटेंट और कंट्रैक्टर आदि के साथ स्थल पर ही बैठक कर विस्तारपूर्वक चर्चा की। निगम आयुक्त चौधरी ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के संतंध में निगम अधिकारियों एवं कंसलटेंट से जानकारी प्राप्त की तथा तैयार ड्राइंग के अनुसार खुदाई आदि कर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त चौधरी ने भवन में लगने वाले दरवाजे, खिड़कियों, फर्नीचर एवं टाइल्स आदि की क्वालिटी के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा की। निगम आयुक्त चौधरी ने भवन के बाहरी क्षेत्र में सड़क, नाली निर्माण एवं बाउंड्रीवाल निर्माण सहित अन्य प्रस्तावित कार्यों की साप्ताहिक कार्य योजना अनुसार चार सप्ताह की योजना बनाकर तीव्र गति से कार्य पूर्ण

करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त चौधरी ने जलप्रदाय व्यवस्था के अंतर्गत जोन क्रमांक 13 वाई क्रमांक 54 के अंतर्गत साकेत नगर स्थित दुर्गा मंदिर टंकी पर स्थापित 60 एचपी पम्पों एवं जोन क्रमांक 15 वाई क्रमांक 63 के अंतर्गत रत्नागिरी स्थित उच्च स्तरीय टंकी परिसर में 10 लाख लीटर क्षमता के निर्माणाधीन सम्पटैंक एवं पम्प हाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधीक्षण यंत्री उदित गर्ग, कार्यपालन यंत्री प्रमोद मालवीय सहित निगम के अन्य अधिकारी मौजूद थे। निगम आयुक्त के.वी.एस. चौधरी ने शुक्रवार को निर्माणाधीन निगम मुख्यालय भवन का निरीक्षण किया और भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल एवं ऑडिटोरियम के प्रचलित एवं प्रस्तावित कार्यों के संबंध में अधिकारियों, इंजीनियर, कंसलटेंट और कंट्रैक्टर आदि के साथ स्थल पर ही बैठक कर प्रत्येक कार्य के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा की। निगम आयुक्त चौधरी ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के संबंध में निगम अधिकारियों एवं



कंसलटेंट से जानकारी प्राप्त की तथा तैयार ड्राइंग के अनुसार चिह्नित स्थल पर खुदाई कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त चौधरी ने भवन हेतु दरवाजे, खिड़कियों, फर्नीचर एवं टाइल्स आदि की क्वालिटी के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा की। निगम आयुक्त चौधरी ने जियो थर्मल एवं एयरकंडीशनर आदि कार्यों को प्रारंभिक तैयारी करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त चौधरी ने स्ट्रक्चर एवं स्लैब आदि कार्यों को जून माह तक की समय अवधि में पूर्ण करने के

निर्देश दिए। निगम आयुक्त चौधरी ने जलप्रदाय व्यवस्था के अंतर्गत जोन क्रमांक 13 वाई क्रमांक 54 के अंतर्गत साकेत नगर स्थित दुर्गा मंदिर टंकी स्थित पम्प हाउस में स्थापित किये गये 60 एचपी पम्पों का जायजा लिया एवं अधिकारियों से जलप्रदाय के संबंध में जानकारी प्राप्त की। निगम आयुक्त के अवगत कराया गया कि साकेत नगर एवं नारायण नगर स्थित क्षेत्रों में वर्तमान तक बायपास स्पलाई की जाती थी जिससे क्षेत्रों के रहवासियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा

था। नागरिकों की समस्या के दृष्टिगत् लगभग 24 लाख रूपये की लागत से सम्पटैंक की मरम्मत, विद्युत ट्रांसफॉर्मर स्थापना, 60 एच.पी. के 02 नये पम्पों की स्थापना तथा टंकी से कनक्टिविटी आदि कार्य कराये गए हैं। निगम आयुक्त चौधरी ने जोन क्रमांक 15 वाई क्रमांक 63 के अंतर्गत रत्नागिरी स्थित उच्चस्तरीय टंकी के निर्माणाधीन सम्पटैंक एवं पम्प हाउस का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। निगम आयुक्त को अवगत कराया गया कि रत्नागिरी स्थित 14 लाख लीटर क्षमता की उच्चस्तरीय टंकी के माध्यम से वाई क्रमांक 62, 63 एवं 64 के बालविहार, गादियापुरा, बिजली कालोनी, आनंद नगर, पुराना शिवनगर, रत्नागिरी स्थित मल्टी, गुप्ता कालोनी, सेंट पाल रोड, जेपी कालोनी, मानस विहार एवं अशोक विहार आदि क्षेत्रों के रहवासियों को एक दिन के अंतराल से जलप्रदाय किया जाता है जिसके कारण उक्त क्षेत्रों में जल समस्या बनी रहती थी। नागरिकों की समस्या के

मां तुझे प्रणाम योजना में 120 लाड़ली लक्ष्मियां 1 जून को जाएंगी वाघा - हुसैनी वाला बार्डर

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुसार युवाओं में देश की सीमाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने, राष्ट्र के प्रति समर्पण और युवाओं को सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों के प्रति आकर्षित करने के उद्देश्य से मां तुझे प्रणाम योजना की शुरूआत वर्ष 2013 में की गई। योजना में प्रदेश की 120 लाड़ली लक्ष्मी बेटियाँ 1 जून 2023 को वाघा-हुसैनीवाला परिसर में 10 लाख लीटर क्षमता के निर्माणाधीन सम्पटैंक एवं पम्प हाउस का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। निगम आयुक्त को अवगत कराया गया कि रत्नागिरी स्थित 14 लाख लीटर क्षमता की उच्चस्तरीय टंकी के माध्यम से वाई क्रमांक 62, 63 एवं 64 के बालविहार, गादियापुरा, बिजली कालोनी, आनंद नगर, पुराना शिवनगर, रत्नागिरी स्थित मल्टी, गुप्ता कालोनी, सेंट पाल रोड, जेपी कालोनी, मानस विहार एवं अशोक विहार आदि क्षेत्रों के रहवासियों को एक दिन के अंतराल से जलप्रदाय किया जाता है जिसके कारण उक्त क्षेत्रों में जल समस्या बनी रहती थी। नागरिकों की समस्या के

सम्पादकीय

चीता प्रोजेक्ट ...उठते सवाल

मध्य प्रदेश के कूनों नेशनल पार्क में बड़े जोरशोर से अफ्रीका से चीते लाए गए थे, लेकिन यहां के वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञों के सारे दावे फेल हो गए और अब तक तीन चीते और तीन शावकों की मौत हो चुकी है। मादा चीता ज्वाला के एक–एक कर तीन शावकों की मौत ने जहां वन्य जीव प्रेमियों को मायूस किया है, वहीं अफ्रीका से चीते लाकर भारत के जंगलों को आबाद करने के इस प्रॉजेक्ट को सवालों के घेरे में भी ला दिया है।

असल में इस महत्वाकांक्षी प्रॉजेक्ट के तहत नामीबिया से 20 चीते लाए गए थे। पहली खेप के चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों



नेशनल पार्क में छुड़वाया गया था। अच्छी धूमधाम हुई थी। बहुत बड़ा इवेंट हुआ। फटाफट चीतों के नामकरण भी हो गए, लेकिन पिछले छह महीने में पहले तीन चीतों की मौत हुई। यहां आने के बाद 27 मार्च को ज्वाला ने चार शावकों को जन्म दिया था, जिसमें से तीन की मौत हो चुकी है।

हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे प्रॉजेक्टों का मूल्यांकन करते हुए जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से बचा जाना चाहिए। न तो एकाध चीतों का जन्म इन प्रॉजेक्टों की सफलता का सबूत होता है और न कुछ चीतों की मौत इनकी नाकामी का ऐलान। लेकिन सवाल तो उठता ही है और उठेगा भी, कि एकाध मौत होती तो ठीक, कुल छह मौतें हो चुकी हैं। कहीं न कहीं कुछ वजह तो होगी ही। अगर इन मौतों ने जीव विज्ञानियों के बीच चिंता पैदा की है तो उसकी वजह इन मौतों के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे कारकों में देखी जा रही है। मध्य प्रदेश वन विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को हुई इन मौतों का कारण गर्मी, कुपोषण और उपचार के प्रयासों पर इनका कोई रेस्पॉन्स न देना बताया है। क्या इसका मतलब यह है कि इन चीतों और शावकों के लिए यहां का मौसम और परिवेश अपेक्षा से कहीं ज्यादा प्रतिकूल साबित हो रहा है? जानकारों के मुताबिक, आम तौर पर संरक्षित क्षेत्र में चीते के शावकों का सरवाइवल रेट काफी अच्छा होता है।

इस उम्र में शावकों के लिए सबसे पौष्टिक आहार मां का दूध होता है। करीब दो महीने की उम्र के ये शावक अगर कमजोर थे तो क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें मां का पर्याप्त दूध नहीं मिल रहा था और अगर यह सच है तो क्या इसके पीछे कारण यह है कि मां में पर्याप्त दूध बन ही नहीं रहा था? इन सवालों के प्रामाणिक जवाब मिलने इसलिए भी मुश्किल हैं क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि इन शावकों और मादा चीता पर कैसे और कितनी नजर रखी जा रही थी।

विशेषज्ञों के मुताबिक, चीता शावकों के पालन–पोषण में इंसानी दखल एक सीमा से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे इनकी शिकार करने की क्षमता प्रभावित होती है। चूँकि इन्हें वन्य जीव के रूप में विकसित होना है, इसलिए इन्हें प्रतिकूलताओं से खुद जूझना और उनसे पार पाना सीखने देना बेहतर माना जाता है। विशेषज्ञ अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन चीतों और यहां पैदा हुए शावकों की मौत अपनी जगह है। मौतों का सिलसिला इन विशेषज्ञों की चिंता या सलाह तो नहीं रोक पा रही है।

वैसे हमारे देश में पुराने तमाम अनुसंधान और शोधों को बेकार घोषित कर पाठ्यक्रम से बाहर किया जा रहा है, जबकि हरेक अनुसंधान और अध्ययन का अपना स्थान होता है। इसका जिक्र इसलिए करना जरूरी है, क्योंकि हम डार्विन के मानव विकास सिद्धांत को नकार चुके हैं, जिसका अपना महत्व है। भले ही चीतों के कूनों में संरक्षण से इसका सीधा संबंध नहीं हो, लेकिन विकास के सिद्धांतों में जलवायु, मिट्टी, तापमान आदि का अपना महत्व होता है। और यदि हम ये कहें कि अफ्रीका के चीतों को भारत में वहां का पूरा वातावरण नहीं मिल सकता, तो विशेषज्ञों को भी आपत्ति हो सकती है। लेकिन आज हम जिन तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनकी अधिकांश समस्याओं के पीछे पारिस्थिकी, जलवायी और भौगोलिक परिस्थितियों में बदलाव ही जिम्मेदार माना जा रहा है। उदाहरण के तौर पर हम मोटे अनाज की तरफ वापस जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बाहर से आया गेहूं हमें तमाम बीमारियां परोस चुका है।

अफ्रीकी चीतों को लेकर बारीकी से अध्ययन होना चाहिए। हम अपने पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए जंगलों को आबाद करना चाहते हैं तो केवल चीते इसके लिए जरूरी नहीं हैं। उनके लिए वैसा ही वातावरण भी बनाना होगा, जिसमें वे जिंदा रह सकें। जंगलों को तो हम कांक्र्रीट के जंगलों में बदल रहे हैं। पहाड़ों को निगलते जा रहे हैं। पर्यटन का भी इसमें योगदान है और धर्म का भी। हमें बुरा तो लगता है, लेकिन सच कड़वा ही होता है। सच यह है कि हम अपनी कन्न स्वयं खोद रहे हैं। चीतों की मौत हमें एक साथ कई संदेश देती है। एक तो शोध और अध्ययन ठोस हो। किसी की बेहतर सलाह भी मान लेना चाहिए। हर जगह राजनीति नहीं होना चाहिए। कूनों भी जैसे राजनीति का एक हिस्सा बना दिया गया। इवेंट पसंद लोगों को पता होना चाहिए कि प्रकृति उनके हिसाब से नहीं चलेगी।

न्यायपालिका और प्रशासन तंत्र की प्रतिबद्धता पर टकराव गंभीर

आलोक मेहता

एक बार फिर संविधानिक शक्तियों के अधिकार ,टकराव , समर्पण का विवाद गर्मा गया है। केंद्र की भाजपा सरकार ही नहीं अन्य राज्यों की अन्य दलों के नेता प्रशासन तंत्र पर नियंत्रण और अफसरों से राजनैतिक प्रतिबद्धता की अपेक्षा कर रहे हैं। न्यायपालिका अधिक सक्रिय होकर सरकारों को नए नए दिशा निर्देश तक दे रही है। ऐसा नहीं है कि यह भारत की समस्या है। अमेरिका में तो सर्वोच्च अदालत के जज तक राष्ट्रपति और संसद की स्वीकृति से बनते हैं। पाकिस्तान में तो निचली और उच्चतम अदालत , सत्तारूढ़ नेता और प्रतिपक्ष के नेता तथा सेना के बीच झूल रही है। इसराइल में जनता का एक वर्ग न्यायिक आजादी के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन कर रहा है। लेकिन भारत की स्थिति सारे विवादों के बावजूद नरम गरम होकर निरंत्रित है। इसलिए केंद्र के कानून मंत्री किरण रिंजिजू को अचानक हटाए जाने और प्रशासनिक राजनैतिक अनुभव वाले अर्जुन राम मेघवाल को मंत्रालय दिए जाने से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच दिख रहा टकराव थमने की उम्मीद की जा सकती है। वैसे रिंजिजू और मेघवाल को लोक सभा चुनाव के लिए पूर्वोत्तर और राजस्थान में अधिक भूमिका का महत्व भी समझा जाना चाहिए।

अदालत और प्रशासन तंत्र के मुद्दे पर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली अखाड़ा बन गया है। अभी मंत्री का बदलाव हुआ और अगले दिन केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत अध्यादेश जारी कर सरकार और संसद के अधिकार का उपयोग कर लिया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को अधिकारियों के तबादले का अधिकार मिले अभी आठ दिन ही हुए थे कि केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिये यह अधिकार फिर उप राज्यपाल को सौंप दिए। इस अध्यादेश के तहत केंद्र सरकार ने दिल्ली में अफसरों के तबादले–नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया है। मुख्यमंत्री प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होंगे, जबकि दिल्ली के प्रधान गृह सचिव पदेन सदस्य–सचिव होंगे। मुख्य सचिव भी इसके सदस्य होंगे। यही प्राधिकरण सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर तबादले की सिफारिश करेगा, पर आखिरी फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल का होगा। मुख्यमंत्री तबादले का फैसला अकेले नहीं कर सकेंगे। मतभेद होने की स्थिति में एलजी का फैसला फाइनल होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की पावर दिल्ली सरकार के पास रहेगी। केंद्र ने अध्यादेश के जरिए कोर्ट का फैसला पलट दिया है। बाद में संसद में इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील रहे अधिपेक मनु सिंघवी ने इस अध्यादेश को बेहद खराब तरीके से बनाया गया करार दिया।

राकेश दुबे देश की नयी संसद के उद्घाटन को लेकर जिस तरह विवाद सामने आ रहे हैं, उसे भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। अब देश के 20 राजनीतिक दलों ने नये संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है, तो लगभग 25 दलों द्वारा इस समारोह के समर्थन का प्रचार किया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक अंग है। इस उद्घाटन विवाद में देश के राष्ट्रपति को भी शामिल कर लिया गया है। यही से राजनीति शुरू हुई है, जो नहीं होना चाहिए थी। इस विषय को लेकर सर्वोच्च न्यायालय पहुँचे, अधिवक्ता ने अपना वाद भी वापिस ले लिया।

विपक्ष दलों की दलील है कि राष्ट्रपति के बिना संसद कार्य नहीं कर सकती। उनके बिना नये संसद भवन का उद्घाटन संविधान के पाठ और उसकी भावना का उल्लंघन है। उनकी दलील है कि भारत के संविधान के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। वहीं भाजपा नेता पुरानी परंपरा का हवाला देकर कह रहे हैं कि आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद की एनेक्स बिल्डिंग की आधारशिला रखी थी व राजीव गांधी ने 1987 में संसद के पुस्तकालय भवन का शिलान्यास किया था। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी विपक्ष से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आह्वान करते हुए विपक्ष द्वारा गैर मुद्दे को मुद्दा बनाने की बात कह रहे हैं। उनका मानना है कि लोकसभा अध्यक्ष संसद के संरक्षक हैं। अध्यक्ष ने ही

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, ग्रीन टेक्नॉलजी से कैसे बदलने जा रही है रोजगार की दुनिया

सादिया जाहिदी पिछले दो साल दुनिया भर के श्रमिकों के लिए यूथल–पुथल भरे रहे। महामारी और उसके बाद यूक्रेन–रूस युद्ध के चलते वास्तविक मजदूरी में गिरावट आई। जेनरेटिव एआई (टेक्स्ट, इमेज आदि कंटेंट मुहैया कराने वाली आर्टिफिशल इंटेलिजेंस) के आने से खास तौर पर वाइट कॉलर जॉब्स में बदलाव की एक नई लहर का अंदेश पैदा हो गया है। ग्रीन एनर्जी को अपनाने पर भी जोर बढ़ा है। इससे ऐसे उद्योग जिनसे अधिक प्रदूषण होता है, वहां भी छंछनी के आसार बढ़ रहे हैं। ऐसा होना बदलाव श्रमिकों के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। वहीं, इन सबके मिले–जुले असर की बात की जाए तो आजीविका का व्यापक संकट दिखता है।

आने वाले पांच साल मजदूर दिवस के मौके पर जारी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम की भविष्य रोजगार रिपोर्ट 2023 अगले पांच वर्षों के दौरान मैक्रो ट्रेंड्स और टेक्नॉलजी में बदलावों के रोजगार और कौशल पर पड़ने वाले असर का लेखा–जोखा तैयार करती है। इसके आकलन के कुछ पहलू खास तौर पर ध्यान देने लायक हैं।

आने वाले पांच वर्षों में दुनिया भर में 23 फीसदी रोजगार बदल जाएंगे। 67.3 करोड़ श्रमिकों वाली 45 अर्थव्यवस्थाओं में 6.9 करोड़ नए रोजगार बनने की संभावना है। 8.3 करोड़ नौकरियां खत्म होने के आसार हैं। यानी नौकरियों में कुल 1.4 करोड़ की कटौती

उन्होंने लिखा, अध्यादेश जिस व्यक्ति ने तैयार किया है उसने बेहद आसानी से कानून की अवहेलना की है। सिविल सेवा पर दिल्ली सरकार को अधिकार संविधान पीठ ने दिया था जिसे अध्यादेश के जरिये पलट दिया गया। संघवाद संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है जिसे नुकसान पहुंचाया गया है। चुनी हुई सरकार के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही को सिर के बल पलट दिया गया। अब दिल्ली सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट की



अवमानना के तर्क पर अदालत की शरण ले सकती है। अदालत से टकराव पिछले महीनों में बढ़ता गया । रिंजिजू जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की खुलकर आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने इसे संविधान से अलग भी करार दिया। कहा जाने लगा कि केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति में अपनी भूमिका चाहती है। हाल के महीनों में मोदी सरकार के मंत्री रिंजिजू जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे थे, उसने शायद सरकार को असहज कर दिया। हालात ऐसे बन गए कि सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिंजिजू द्वारा कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ की गई टिप्पणी पर कार्रवाई की मांग की जाने लगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि उसके पास इससे निपटने के लिए व्यापक दृष्टिकोण है। रिंजिजू ने कहा था कि जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली पारदर्शी नहीं है। न्यायपालिका बनाम सरकार की बातें जब मीडिया में आतीं तो रिंजिजू सफाई भी देते कि लोकतंत्र में मतभेद अपरिहार्य हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार और न्यायपालिका के बीच मतभेदों को टकराव नहीं माना जा सकता है।सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज कोई सरकार नहीं हैं? जजों की नियुक्ति का कॉलेजियम सिस्टम संविधान के लिए एलियन हैं? जजों के लंबी छुट्टी पर जाने से कोर्ट में मामले लॉबित होंगे। '

कॉलेजियम सिस्टम के विरोध में रिंजिजू ने दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज आर.एस. सोढ़ी के इंटरव्यू का अंश ट्वीट किया। न्यायमूर्ति सोढ़ी (सेवानिवृत्त) कहते हैं कि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है और सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। सोढ़ी ने

लोकतंत्र के मंदिर संसद पर राजनीति न करें

प्रधानमंत्री को उद्घाटन के लिये आमंत्रित किया है । संसद भवन का यह उद्घाटन एक ऐतिहासिक घटना है और प्रत्येक घटना का राजनीतिकरण करना उचित है यह देश के राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए ।इस नये संसद भवन का निर्माण कार्य 2021 में आरंभ हुआ था और 28 महीने में इसे पूरा कर लिया गया। अब 28 मई को इस नये भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। सरकार की तरफ से कहा गया है कि नये संसद भवन का निर्माण साठ हजार श्रमयोगियों ने किया है। उल्लेखनीय है कि 19 पार्टियों द्वारा बहिष्कार के बावजूद अकाली दल, बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेंगी। विपक्ष के विरोध का एक कमजोर तर्क यह भी है कि 28 मई को हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है और यह राष्ट्र निर्माताओं के धर्मनिरपेक्ष विचार के विपरीत है।कमजोर इसलिए कि राजनीति स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष को ही याद रखना चाहती है।

विपक्ष यह भी आरोप लगाता है कि प्रधानमंत्री इवेंट मैनेजमेंट के जरिये राजनीतिक लाभ लेने के प्रयास में हमेशा रहते हैं। वे अन्य लोगों को इसका मौका नहीं देते। कांग्रेस समेत विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति इस देश की प्रमुख हैं। आदिवासी महिला होने के साथ संसद की संरक्षक भी हैं। उनके हाथों नये संसद भवन का उद्घाटन कराना प्रोटोकॉल का तकाजा भी है। प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन से यह कार्यक्रम एक पॉलिटिकल इवेंट बन जायेगा। उनकी दलील है कि नया संसद भवन एक इमारत मात्र नहीं है। यह

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, ग्रीन टेक्नॉलजी से कैसे बदलने जा रही है रोजगार की दुनिया

होगी। भारत में 22 फीसदी रोजगार बदलेंगे। इनमें 12 फीसदी की बढ़ोतरी होगी तो 10 फीसदी रोजगार कम होगा। नई टेक्नॉलजी अपनाते से करीब एक चौथाई कंपनियों में रोजगार कम होंगे, जबकि आधे से ज्यादा कंपनियों में रोजगार बढ़ेंगे। लेकिन इंसान–मशीन मोर्चे पर हालात बिल्कुल अलग मोड़ लेने वाले हैं। मशीनों की वजह से शारीरिक काम छिन्ने की स्थितियां कम होंगी, लेकिन ऐसे काम जिनमें तर्क, संवाद और समन्वय की जरूरत होती है, मशीनों के हिस्से जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं।

सर्वे में शामिल 75 फीसदी कंपनियों में जेनरेटिव एआई अपनाई जाने वाली है और इससे भी नौकरियों पर कम खतरा नहीं है। खासकर बैंक कैशियर, क्लर्क, सेक्रेटरी और अकाउंटिंग जैसे काम इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। फिर भी रोजगार छिन्ने के पीछे सबसे बड़ी भूमिका होगी आर्थिक सुस्ती, लागत में बढ़ोतरी और कम होती मांग की स्थिति।

जिन स्किल्स की मांग सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, उनमें रचनात्मक और विश्लेषणपरक चिंतन, तकनीकी साक्षरता, जिज्ञासा और एआई शामिल हैं।

भारत में कामगारों के बुनियादी स्किल्स में 46 फीसदी बदलाव होगा, जो वैश्विक औसत से ज्यादा है। कंपनियां श्रमिकों को स्किल में बेहतरी की लेकर प्राथमिकताएं तय कर रही हैं। इनमें से 60 फीसदी स्किल में आए गैप से परेशान हैं तो 54 फीसदी की फिक्र यह है कि प्रतिभाशाली लोगों को कैसे आकर्षित किया जाए। ऐसे में वर्कर, एम्प्लॉयर और सरकार भविष्य के रोजगार के लिए तैयारी कैसे करें?

कहा था कि क्या आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं? केवल संसद ही संविधान में संशोधन करेगी। जब कोई जज बनता है तो उसे चुनाव का सामना नहीं करना पड़ता। जजों के लिए कोई सार्वजनिक जांच भी नहीं होती।

रिंजिजू ने यह भी कहा था कि भारतीय न्यायपालिका में कोई आरक्षण नहीं है। मैंने सभी जजों और विशेष रूप से कॉलेजियम के सदस्यों को याद दिलाया है कि वे पिछड़े समुदायों, महिलाओं और अन्य श्रेणियों के सदस्यों को शामिल करने के लिए नामों की सिफारिश करते समय ध्यान में रखें क्योंकि उनका न्यायपालिका में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रोहिटन फली नरीमन ने कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बोलने पर कानून मंत्री रिंजिजू की आलोचना की थी। उन्होंने जजों की नियुक्ति में केंद्र के दखल को लोकतंत्र के लिए घातक बताया। कॉलेजियम के नामों को सरकार द्वारा कथित तौर पर लटकाने पर भी काफी विवाद हुआ। रिंजिजू के बयानों को सुनकर विपक्ष कहने लगा कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को धमकाया जा रहा है।

संविधान में उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका (सरकार) को प्राथमिकता दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 124 (2) के मुताबिक ‘उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा, 'संवैधानिक भाषा में इस अनुच्छेद में जो लिखा है, उसका मतलब है कि राष्ट्रपति जजों की नियुक्त के लिए जजों से परामर्श ले सकता है। इसमें राष्ट्रपति की सर्वोच्चता निहित है।

ये व्यवस्था 1993 तक चलती रही. हालांकि, इस बीच जजों की नियुक्तियों से संबंधित कई विवाद हुए जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच खींचतान भी शामिल है। 1981 में पहले जजेज केस में परमर्श का अर्थ राय–विचार लेना बताया गया, लेकिन 1993 में दूसरे जजेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला बदल दिया और परामर्श का मतलब ‘सहमति’ बताया। आम भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि जजों की नियुक्ति के लिए जजों की सहमति चाहिए यानी जज जिसे कहेंगे, उन्हें राष्ट्रपति जज नियुक्त करेंगे। इसी फैसले से कॉलेजियम सिस्टम अस्तित्व में आया। 1998 में तीसरे जजेज केस में कॉलेजियम सिस्टम की कार्यप्रणाली का निर्धारण हुआ।

ऐसा माना गया कि इस व्यवस्था में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वायत्तता की रक्षा होगी और

सरकार के हस्तक्षेप से न्यायपालिका को बचाया जा सकेगा. चूँकि इससे पहले, खासकर इंदिरा गांधी के शासनकाल में सरकार द्वारा न्यायपालिका को प्रभावित करने के मामले हुए थे, इसलिए जनमत भी इस पक्ष में था कि न्यायपालिका को सरकार के हस्तक्षेप से बचाया जाए। इसलिए उस दौर में, कॉलेजियम सिस्टम का खास विरोध भी नहीं हुआ। लेकिन बाद में कॉलेजियम सिस्टम की बुराइयां सामने आने लगी। राजनेता ही नहीं पूर्व न्यायाधीश और कई बड़े वकील इस व्यवस्था की गड़बड़ियां गिनाने लगे। न्यायपालिका में फैसले देने की रफ्तार बेहद सुस्त पड़ गई। कई विवाद भी हुए, इस कारण न्यायपालिका की बदनामी हुई है और जजों के टकराव से न्यायपालिका कई बार संकट में भी आई। आलोचकों ने इस व्यवस्था की कमिया गिनाई ‘कॉलेजियम सिस्टम संविधान की व्यवस्थाओं के खिलाफ है क्योंकि जजों की नियुक्ति जजों का नहीं, सरकार का काम है. जजों द्वारा जजों की नियुक्ति का सिस्टम दुनिया में कहीं और नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम के कारण जजों के बीच आपसी पॉलिटिक्स होती है और जज फैसला लिखने से ज्यादा ध्यान इस बात पर लगाते हैं कि कौन जज बने. इस वजह से जजों के बीच गुटबाजी होती है और नियुक्तियों में देरी होती है। इस सिस्टम में भाई–भतीजावाद है क्योंकि ज्यादातर जज अपने रिश्तेदारों और जान–पहचान वालों की ही सिफारिश जज बनाने के लिए करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम आने से पहले यानी 1993 से पहले जो व्यवस्था थी, उससे बेहतर जज बन रहे थे और विवाद भी कम होता था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत में ही कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार, विपक्ष और जानकारों को शामिल करने के आयोग बनाने की व्यवस्था लाने की कोशिश की थी, इसके लिए संविधान संशोधन भी किया गया और नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कानून, 2014 भी पारित किया गया. लेकिन तब वे नए–नए आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। अब जबकि कॉलेजियम सिस्टम की बुराइयां उभरकर सामने आ गई हैं, तब सरकार इस मसले पर फिर विचार कर रही है। संभव है कि उसका इरादा नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कानून को नए सिरे से लाने का हो और संसद में प्रस्ताव लाया जाए। देश के इतिहास में अलग–अलग समय पर न्यायपालिका की अलग–अलग प्रतिक्रिया के बावजूद ये पूरी तरह स्पष्ट है कि उसने भारत में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मजबूती एवं रक्षा करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अब समय आ गया है जब हर संस्थान के सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर आत्मनिरीक्षण हो और उसका एक समाधान तलाशने की जरूरत है।

लोकतंत्र के मंदिर संसद पर राजनीति न करें

प्राचीन परंपराओं, मूल्यों के साथ ही भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद भी है। वहीं सरकार कहती है कि देश में बढ़ती आबादी के साथ नये लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन होता है तो उसके अनुरूप भविष्य में संसद में अधिक सांसदों के बैठने की जगह होनी चाहिए। ताकि संसद का कार्य सुचारु रूप से चल सके। साथ ही सांसदों से जुड़े विभागों के कार्यालयों के एक ही जगह होने से कार्यप्रणाली को सुचारु बनाया जा सकेगा।

नये संसद भवन के लोकसभा कक्ष में 888 सदस्य और राज्यसभा कक्ष में तीन सौ सदस्य आराम से बैठ सकेंगे। नये संसद भवन को चार मंजिला व भूकंपरोधी बनाया गया है। जिसमें तीन मुख्य द्वारों को जान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। उल्लेखनीय है कि नये लोकसभा भवन में इतनी जगह होगी कि दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाया जा सकेगा। सरकार का तर्क है कि ब्रिटिश राजसत्ता के दौरान निर्मित मौजूदा संसद भवन 96 साल पहले 1927 में बनाया गया था और उसका अधिकतम उपयोग हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद नये संसद भवन का उद्घाटन यदि सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी व सहमति से होता तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रेरक छवि उभरती। संसद देश के एक सी चालीस करोड़ से अधिक लोगों के लिये लोकतंत्र का मंदिर है।?उसकी शुचिता–गरिमा को बनाये रखना सभी राजनीतिक दलों का दायित्व भी है। सत्तापक्ष व विपक्ष को इसका ध्यान रखना होगा।

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, ग्रीन टेक्नॉलजी से कैसे बदलने जा रही है रोजगार की दुनिया

टेक्नॉलजी की प्रधानता, हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने और वैश्वीकरण घटने वाले दौर में लोकल स्किल डिवेलपमेंट सबसे ज्यादा काम आएगा। एनालिटिकल और इंटरपर्सनल स्किल और टेक्नॉलजी के साथ काम को सम्झने की क्षमता काफी अहम होगी। हर स्टूडेंट को, चाहे उसका क्षेत्र कोई भी हो, इन स्किल को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। जो क्षेत्र उतार पर हैं, उनके मजदूरों की रीस्किलिंग और ट्रांजिशन के प्रयासों पर खासा जोर देने की जरूरत है।

जो क्षेत्र बढ़त पर हैं उनमें लगातार सीखने की क्षमता विकसित करने पर ध्यान देना होगा। स्किल में बेहतरी के लिए सरकारों को ही संसाधन और रोज़मैप मुहैया कराना होगा। नई टेक्नॉलजी को सुरक्षित बनाने के लिए नियम–कानूनों में जरूरी बदलाव सुनिश्चित करना और श्रमिकों की सहायता दोनों जरूरी हैं और इनके बीच संतुलन बनाए रखना सरकारों के लिए बड़ी चुनौती होगी।

एम्प्लॉयर्स की चुनौती एम्प्लॉयर्स को भी अपने लेवल पर रीस्किलिंग और और अप्रिस्किलिंग में निवेश करना होगा। ज्यादातर एम्प्लॉयर्स की अपेक्षा रहती है कि निवेश पर एक साल के अंदर रिटर्न मिलने लगे। लेकिन सर्वश्रेष्ठ एम्प्लॉयर्स आगे बढ़कर कंपनी से बाहर भी वर्कर्स को स्किल बढ़ाने में मदद करते हैं और भर्ती के दौरान शैक्षणिक योग्यता या पहले के काम के बजाय स्किल को शीर्ष प्राथमिकता देते हैं।

देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट सिटी कन्वेंशन का मव्य आयोजन

नई दिल्ली, एजेंसी। जमीन पर आकार लेने वाले सपनों को पूरा करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं रियलस्टेट। रियल एस्टेट का क्षेत्र बाहर से जितना ग्लैमरस दिखता है, उतनी ही ज्यादा मेहनत भी मांता है। निरन्तर समय के साथ अपडेट रहना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट्स पर काम करना, क्लाइट्स की परफं और मांग के मुताबिक समाधान प्रस्तुत करना और समय के हिसाब से बदलती चुनौतियों का सामना करना, एक रियाल्टर की ज़िंदगी का हिस्सा होता है। इन सभी पहलुओं पर सार्थक चर्चा करने, समाधानों पर बात करने और रियाल्टर्स को लाइफ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मंत्र देने के लिए शहर में किया गया, देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट सिटी कन्वेशन बीइंग रियाल्टर का आयोजन। इंदौर रियाल्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन व नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियाल्टर्स-इंडिया द्वारा ब्रिलियंट कन्वेशन सेंटर में इस आयोजित इस कार्यक्रम की प्रशंसा देशभर से आये रियाल्टर्स, ख्यातनाम मोटिवेशनल स्पीकर्स और सभी अतिथियों ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव व भाजपा महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय थे। श्री विजयवर्गीय ने शहर से बाहर होने के कारण ऑनलाइन ही कार्यक्रम में मौजूद लोगों से रूबरू हुए और उन्होंने इंदौरी खाने से लेकर तेजी से बदल रहे शहर के नाइट कल्चर के बारे में बात की। महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव ने कहा-रियल स्टेट के साथ साथ हम रियली स्टेट (सम्पूर्ण राज्य का विकास) का विकास करने की भी लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। केवल साफ्य ही नहीं बल्कि हर स्तर पर हम इंदौर को ऐसा बनाना चाहते हैं कि देशभर से लोग यहाँ आये और बस जाएँ।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया नया डेट फंड

रीवा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने सोमवार को एक डेट फंड लॉन्च किया। यह फंड ग्राहकों को मौजूदा कुछ ब्याज दरों पर अपने निवेश को लॉक करने, लंबी अवधि में धन का निर्माण करने और वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में सक्षम बनाएगा। प्रचलित ब्याज दर व्यवस्था ग्राहकों को निवेश करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती है। इस तरह ग्राहक जीवन बीमा बाजार में इस तरह के पहले डेट फंड - आईसीआईसीआई पू कॉन्सटेंट मेच्योरिटी फंड में निवेश कर सकते हैं। वर्तमान दौर में ब्याज दर बेहद ऊंची हैं, लेकिन ब्याज दरों में कोई भी गिरावट होती है, तो डेट फंड अपने ग्राहकों के लिए एक आकर्षक निवेश विकल्प के रूप में सामने आते हैं। डेट इंस्ट्रुमेंट्स और ब्याज दरों की कीमतों के बीच विपरीत संबंधों के कारण ऐसा होता है - जब ब्याज दरें गिरती हैं तो डेट इंस्ट्रुमेंट्स की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे उन ग्राहकों को फायदा होता हैजिन्होंने इन इंस्ट्रुमेंट्स में निवेश किया है। यह फंड कंपनी के प्रमुख यूनिट लिंकड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) में निवेश के लिए उपलब्ध है।

अमेजन प्राइम का नया सच में टू मच कैपेन दिखाता है ज्यादा की खुशी

मुंबई, एजेंसी। शापिंग से लेकर एंटरटेनमेंट तक बेनेफिट्स के अद्वितीय संयोजन के साथ ग्राहकों को खूब सारी खरीदारी के लिए सक्षम बनाने के लिए, अमेजन प्राइम एक मूल्यवान मेंबरशिप है, जो प्रत्येक ग्राहक के जीवन में ज्यादा की खुशी को सुनिश्चित करता है। नया विज्ञापन अभियान ग्राहकों से अपने प्राइम मेंबरशिप से अधिकतम मूल्य प्राप्त करने का आग्रह करता है। एक मेंबरशिप के तहत ढेर सारे लाभों के साथ, अमेजन प्राइम सदस्यों को 40 लाख से ज्यादा उत्पादों पर फ्री वन-डे डिलीवरी, दैनिक घरलू आवश्यकताओं के साथ-साथ फोन, कपड़े, होम डेकोर, ब्यूटी आदि जैसे पसंदीदा उत्पादों पर प्राइम ऑफर के साथ खरीदारी करने में सक्षम बनाता है। इस अभियान में - दो फल्टिमे सेट के साथ- एक अनूठा दृष्टिकोण अपनाया गया है। पहली फल्टिमे में अभी तक प्राइम कस्टमर न बनने वालों को वन मेंबरशिप, मैनी बेनेफिट्स के बारे में बताया गया है, जबकि दूसरी फल्टिमे में मौजूदा प्राइम मेंबर्स को बताया गया है कि कैसे वे अपने अमेजन मेंबरशिप के साथ ढेर सारे लाभों का फायदा उठा सकते हैं।

ग्रेविटा ने तंजानिया, पूर्व अफीका में रबड़ रीसाइक्लिंगका व्यापारिक उत्पादन शुरू किया

जयपुर, एजेंसी। विश्व भर में मैनुफैक्चरिंग उपस्थिति रखने वाली एक प्रमुख रीसाइक्लिंग कंपनी,ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड सहस्रं सुचित करती है कि कंपनी की तंजानिया, पूर्व अफ्रीका स्थित स्टेप डाउन सस्टिनेडिग्री,ग्रेविटा तंजानिया लिमिटेड ने चरण प्रथम में लगभग 3000 मेट्रिक टन क्षमता के साथ रैपिड रबड़ की रीसाइक्लिंग करने का व्यापारिक उत्पादन शुरू कर दिया है 7 आगे चलकर ग्रुप ने उक्त क्षमता बढ़ाकर 6000 मेट्रिक टन वार्षिक करने की योजना बनाई है। कंपनी ने प्रथम चरण में सुविधा स्थाा पत करने के लिए 3.86 करोड़ रुपए का पूंजी खर्च किया है, जिसका वित्तपोषण आंतरिक साधनों द्वारा किया गया है। यह नया रीसाइक्लिंग प्लांट ग्रेविटा तंजानिया लिमिटेड की रबड़ रीसाइक्लिंग प्रक्रिया के दौरान उत्सर्जित पायरोलाइसिस आयल के रूप में कार्बन फुटप्रिंट्स में कमी के साथ-साथउसकी उत्पादन लागत में कमी करने में मदद करेगा जिसका कंपनी द्वारा बैटरी और अल्युमिनियम स्क्रीप की रीसाइक्लिंग के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में इन हाउस खपत के लिए उपयोग किया जाएगा।

मैरिंगो सिम्स अस्पताल ने अंगदान के माध्यम से जीवन बचाने वाले वीर परिवार के लिए सम्मान व्यक्त किया

अहमदाबाद/मुंबई, एजेंसी। भुज के एक परिवार ने अपने परिवार के ब्रेन हेमरेज के कारण अपनी जान गंवा देनेवाले युवा सदस्य के अंगों को दान करने में मानवता के अंतिम कार्य का प्रदर्शन किया और अन्तर्गत प्राप्तकर्ताओं के जीवन को बचाया । महिपाल (बदला हुआ नाम) को भुज में काम के दौरान अचानक ब्रेन स्ट्रोक हुआ। उन्हें उनके परिवार द्वारा अस्पताल में ले जाया गया और अंत में मैरिंगो सिम्स अस्पताल लाया गया जहां उन्हें ब्रेन डेड घोषित किया गया।परिवार ने चार लोगों का दान बचाने और दो की दृष्टि बहाल करने के लिए मुक्त के अंगों को दान करने के लिए साहस और मानवता का प्रदर्शन किया। अंगों को पुनः प्राप्त करने के बाद गुर्दे और यकृत तुरंत मैरिंगो सिम्स अस्पताल में भर्ती प्राप्तकर्ताओं में प्रत्यारोपित करने के लिए तैयार हो गए, जबकि दिल और आंखों को क्रमशः एक सरकारी अस्पताल और अर्ध-सरकारी संस्थान में दान कर दिया गया।

2000 नोटबंदी हमारी सोच काली का प्रतीक है

2000 नोटबंदी हमारी सोच काली का प्रतीक है, अन्यथा हमें एक्सचेंज की बजाय सीधे खाले में जमा कराते। जिसके खाले नहीं हैं उसके खाले खोले जाएं, खाले को आधार नंबर से भी जोड़ना जाए खाले में ही पैसा जमा कराए जाएं, जमाकर्ताओं की पहचान? जमा रिलप के साथ स्कैन कर खाले के साथ अटैच की जाए, अन्यथा हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा। जमा करना व निगलाना अलग अलग प्रक्रिया है, यदि उसे पैसे चाहिए तो निकाले। हमारे राजनेताओं की सोच ही काली है, अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अपराध मुक्त भारत मिशन के उभरते चन्द्रगुप्त बिना खर्च व बिना वोट मांगे, मतदान के पूर्व इन्हें अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश कर देंगे।जय हिन्द, जय भारत, वंदेमातरा मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय अध्यक्ष अपराध मुक्त भारत मिशन पूर्व पुलिस महानिदेशक (पुलिस सुधार) मध्यप्रदेश।

आम के बहाने बदलती दुनिया की कुछ खास बातें

जय नागड़ा

बाज़ार आम से पटा हुआ है, लेकिन बेस्वाद ज अच्छे आम की तलाश में आज भरी दोपहर में फ्रुट मार्केट में भी हो आये, बादाम, केसर, लाल पट्टा सभी था दिखने में खूबसूरत लेकिन खाने में लगा कि पहले वाली बात नहीं है ज़ फ्रुट के एक पुराने व्यापारी से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब मिला कच्चे आम को केमिकल से पकाने में हद ऊपर से पीला तो दिखने लगता है लेकिन उसके गुण नहीं आ पाते ज पेड़ पर पकने का इंतज़ार अब कौन करता है ! सबको जल्दी है? व्यापारी को पैसा खड़ा करने की जल्दी है तो ग्राहक को भी अच्छे बुरे की समझ नहीं है !

शाम को बिटिया नेहा से बात हो रही थी, जो एक मल्टीनेशनल कम्पनी में टेलेन्ट डेविक्रेशन की जिम्मेदारी देखती है , कह रही थी कि कम्पनी अब सिर्फ आईआईटी, आईआईएम या किसी बड़े संस्थान की डिग्रियों पर प्लेसमेंट नहीं करती बल्कि यह देखती है कि जिसे बहुत बड़े पैकेज पर अर्पाइंट किया जा रहा है वह मल्टीटास्किंग है या नहीं? ज़हिर है कंपनियों को परफॉर्म करने वालों की जरूरत है बजाय डिग्रीधारियों के जउसने यह भी कहा कि अब जॉब में वे ही ज्यादा सफल हो रहे हैजिनका स्कूलिंग बेहतर हुआ है , जिन्होने सिर्फ नंबर लाने पर नहीं बल्कि पूरी पर्सनाल्टी डेवलेपमेंट पर ध्यान दिया है। स्कूल में सीखी बहुत सी बातें यहाँ व्यावहारिक रूप से काम में आ रही है। त्करीबन यही बात छोटी बिटिया यशस्वी ने भी कही जो बॉश (ब्रम्हहृद्दहृद्द) में यूएक्स एक्सपर्ट के बतौर सेवारात है।

आप सोचेंगे ये दोनों बातों का आपस में क्या साम्य? आम के स्वाद से प्लेसमेंट का क्या सम्बन्ध? हाँ, एक बहुत



गहरा सम्बन्ध है क्वालिटी का, गुणवत्ता का !

यह सच है कि हमारे समाज में सब को हर बात की जल्दी है , मामला खानपान का हो या करियर का ज फ़ास्टफूड संस्कृति के दुष्प्रभाव तो हमने महसूस कर लिया, अब स्वास्थ्य की चिन्ता ने हमें पौष्टिक और स्वास्थ्यप्रद पारम्परिक भोजन शैली की ओर लौटने पर मजबूर कर दिया लेकिन जीवन के अन्य क्षेत्रों में?

दरअसल किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके स्कूल एजुकेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, उसका

डॉलर की बादशाहत को मिल रही चुनौती: वैश्विक लेनदेन में युआन का हिस्सा बढ़ा, अमेरिकी कर्ज संकट ने बढ़ाई मुश्किल

नई दिल्ली , एजेंसी। अमेरिकी

डॉलर की बादशाहत को अन्य प्रमुख मुद्राओं से चुनौती मिलने लगी है। इसकी वजह खुद अमेरिकी नीतियां हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के साथ प्रतिद्वंद्विता, यूक्रेन युद्ध के झटके और अमेरिकी कर्ज संकट ने दुनिया की प्रमुख मुद्रा के रूप में डॉलर की स्थिति पर फिर से विचार करने पर मजबूर किया है।

कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर का विकल्प तलाश रही हैं। रूस, चीन, भारत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश इनमें शामिल हैं। बांग्लादेश जैसे दर्जन भर छोटे एशियाई देश भी स्थानीय मुद्रा में आपसी व्यापार कर रहे हैं।

भारत दरिहम और रूबल में खरीद रहा रूसी तेल- विशेषज्ञों के मुताबिक, वैश्विक व्यापार में उथल-पुथल जारी है। भारत यूएई दरिहम व रूबल में रूसी तेल खरीद रहा है। चीन ने युआन से 88 अरब डॉलर का रूसी तेल, कोयला और धातु खरीदा। वैश्विक विदेशी मुद्रा लेनदेन में युआन की हिस्सेदारी बढ़कर 7 फीसदी पर पहुंच गई है।

फॉरेक्स में डॉलर की हिस्सेदारी 20 साल के निचले स्तर पर- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक, 2022 की चौथी तिमाही में दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का हिस्सा 20 साल के निचले स्तर 58 फीसदी पर आ गया। अब यह और घटकर 1995 के समान स्तर पर आ गया है।

इसलिए भी विश्विक ढूंढ रहे देश- यूरिजोन एसएलजे कैपिटल के सीईओ स्टीफन जेन ने कहा, यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसने सऊदी अरब, भारत, चीन और तुर्किये जैसे देशों को अन्य

पीडब्ल्यू स्किल्स भारत में टेक स्किलिंग के लिए सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा

अब तक 1.5 लाख से अधिक शिक्षार्थियों को सशक्त बनाया; 2025 तक 10 लाख पेशेवरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है

मुंबई , एजेंसी। फ़िजिक्स वाला (पीडब्ल्यू), भारत का अग्रणी एड-टेक प्लेटफॉर्म, अपने स्किलिंग वर्टिकल, पीडब्ल्यू स्किल्स द्वारा हासिल एक उल्लेखनीय उपलब्धि की घोषणा करते हुए ग्वं एवं अनुभव कर रहा है। हिंदी, अंग्रेजी और हिंग्लिश में उपलब्ध कोर्सेज़करा, यह अब 1.5 लाख शिक्षार्थियों को तकनीकी कौशल सिखाने वाला सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन कर उभरा है। इन शिक्षार्थियों में, 50,000 पेड़ बेचों में नामांकित हैं, जबकि शेष मुक्त कोर्सेज़ से लाभान्वित हुए हैं। 30,000 शिक्षार्थी विशेष रूप से, हिंदी हार्टडैड से आते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्य शामिल हैं। महज पांच महीने के भीतर मौल का पथर स्थापित करने वाली इस उपलब्धि को हासिल करना पीडब्ल्यू के मौजूदा कम्युनिटी और डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत का प्रमाण है, जो इसकी ग्रोथ को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं।आधुनिक समय में प्रासंगिक तकनीकी कौशल वाले पेशेवरों की मांग और आपूर्ति के बीच बनी खाई को खत्म करने के मिशन के साथ, पीडब्ल्यू स्किल्स पहले से ही डेटा साइंस, जावा, ए++, फुल-स्टैक वेब डेवलपमेंट में बढ़ाबड़ कोर्सेज़ और अन्य टेक्निकल कोर्स 3,500 से शुरू आकर्षक मूल्यों पर करा रहा है।

विप्स-टीसी और आईआईटी गांधीनगर ने आईटी में प्रौद्योगिकीय उन्नति को गति देने के लिए रणनीतिक साझेदारी की

दिल्ली/एनसीआर, एजेंसी। विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, टेक्निकल कैंपस (विप्स-टीसी) और प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर (आईआईटी गांधीनगर) ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं इससे जुड़े क्षेत्रों में नवप्रवर्तन, अकादमिक उत्कृष्टता एवं अनुसंधान गठबंधन के उद्देश्य से एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने के लिए एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। यह ऐतिहासिक गठबंधन दोनों ही संस्थानों के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए जबरदस्त अवसरों

का सृजन करेगा।इस एमओयू पर आईआईटी गांधीनगर के निदेशक प्रोफेसर रजत मूना और विप्स-टीसी के वाइस चेयरमैन श्री विनीत वत्स ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर विप्स-टीसी के महानिदेशक डॉनरट अश्विनी

और डॉक्टरल प्रोग्राम शुरू करना या सुधार लाना, इंटरशिप प्रोग्राम, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, फैकल्टी सपोर्ट, ढांचागत विकास में मार्गदर्शन और पारस्परिक हित के विषयों पर संघर्षों, सम्प्लेनों, कार्यशालाओं का संयुक्त आयोजन करना है। यह गठबंधन दोनों संस्थानों से शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकीय उद्ययन पर मिलकर काम करने और आईटी क्षेत्र में उपरती चुनौतियों का सामना करने के लिए एक अनूठ अवसर उपलब्ध कराएगा। आईआईटी गांधीनगर के निदेशक प्रोफेसर

कुमार शर्मा, विप्स-टीसी के वाइस चेयरमैन सुनीत वत्स और विप्स-टीसी के वाइस चेयरमैन अजय बिंदल उपस्थित थे।इस एमओयू का उद्देश्य प्रशासनिक सहयोग को सुगम बनाना, विप्स-टीसी में नए स्नातक, स्नातकोत्तर

रजत मूना के मुताबिक, श्रइस एमओयू से विप्स-टीसी, विप्स इंस्टीट्यूट, आईआईटी गांधीनगर के विद्यार्थियों सहित पूरा समाज लाभान्वित होगा। हमारा उद्देश्य इन विद्यार्थियों के लाभ को प्राथमिकता देना है।

सम्पूर्ण व्यक्तित्व का आधार ही स्कूल में तैयार होता है चाहे वह छोटे से गांव का सरकारी स्कूल हो या फिर कोई सर्वसुविधायुक निजी स्कूल।

इस समय बड़ी दिक्कत यह हो रही है कि आठवीं के बाद बच्चे कोचिंग की दौड़ में इस कदर शामिल हो जाते है कि स्कूल हाशिये पर छूटने लगता है। अब तो बड़ी समस्या यह आ रही है कि कोचिंग जाने वाला विद्यार्थी स्कूल से ही पूरी तरह दूर होने लगा है, डमी एडमिशन के विकल्प ने उसे पूरी तरह कोचिंग पर निर्भर कर दिया है। कोचिंग स्टूडेंट्स

मीडियाटेक ने नयी प्रौद्योगिकियों के लिए रूपरेखा तैयार की

स्मार्टफ़ोन, स्मार्ट ड़िवाइस इकोसिस्टम, ऑटोमोटिव, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहित सभी निर्बाध प्रौद्योगिकियों में विस्तार की तैयारी

नयी दिल्ली, एजेंसी। सालाना करीब दो अरब कनेक्टेड उपकरणों को ताकत प्रदान करने वाली विश्व की अग्रणी फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी मीडियाटेक प्द विज्ञान टुगो बियांडविथ ब्रिलियंट टेक्नोलॉजीजपू्थीम पर टेक्नोलॉजी डायरीज्के अपने 12वें चैप्टर की मेज़बानी की जिसमें ऑटोमोटिव, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में मीडियाटेक की नवीनतम प्रौद्योगिकियों पर जोर रहा। मीडियाटेक ने भारत में सभी स्मार्टफ़ोन और स्मार्ट ड़िवाइस इकोसिस्टम में अपनी उपस्थिति बढ़ाने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

मीडियाटेक ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के अपने नवीनतम पोटेंफ़लियो और आने वाले 5 जी चिपसेट को साझा किया जिसमें मीडियाटेक डायमैन्सिटी 9200 प्लस, 9000 प्लस, 8020, 7050, 7200, कापैनियो 1200, मीडियाटेक डायमैन्सिटी ऑटो और मीडियाटेक जीनियो 1200 शामिल हैं। मीडियाटेक ने मोटोरोला, फ़िलफ़ार्ट, एचपी, वनप्लस, लावा, शियाओमी, इनफ़िनिक्स, ओप्पो, वीवो, टेक्नो, रीयल्म, आईफ़्यूओओ और सैमसंग आदि के साथ सभी पोटेंफ़लियो को लेकर कुछ नवीनतम गठबंधन भी सामने रखे। मीडियाटेक इंडिया के प्रबंध निदेशक अंकु जैन ने कहा, ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी का मतलब महज नए उत्पाद और सेवाओं का सृजन नहीं है, बल्कि इसका अर्थ सार्वक आनुभवों का भी सृजन करना है जिनसे लोगों का जीवन समृद्ध हो। मीडियाटेक में हम जो संभव है, उन सीमाओं का

अंतराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन इस बार मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में आईडीवाई 2023 की थीम भी तय, वसुधैव कुटुंबकम के लिये योग का संदेश देगा इस बार भारत

जबलपुर , एजेंसी।

इस बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के 9वें संस्करण का मुख्य आयोजन मध्यप्रदेश के बेहद खूबसूरत और नर्मदा के तटीय शहर जबलपुर में किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के 25वें काउंटडाउन की पूर्व संंध्या पर शुक्रवार को सिकंदराबाद (तेलगाना) में मीडिया से मुख्यातिब केंद्रीय आंध्रुप मंत्री सर्बानंद सोणोवाल ने यह घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की इस बार की थीम भी तय कर दी गई है और अब भारत आईडीवाईके जरिये पूरे विश्व को इस वर्ष -वसुधैव कुटुंबकम के लिये योग- का संदेश देगा। जी20 और शंघाई संगठन देशों का भारत में इस वर्ष उपस्थिति को देखते हुए इस थीम के कई आयाम हैं। भारत वर्ष 2023 में जी 20 और शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहा है और जी 20 के लिये भी वसुधैव कुटुंबकम थीम है।

दो लाख रुपये क्रेडिट कार्ड की यूपीआई से जोड़ने वाला पहला पेमेंट ऐप बना फोनपे

मुंबई, एजेंसी। फोनपे ने दो बड़ी उपलब्धियां हासिल किए जाने का एलान किया है। फोनपे, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस से दो लाख रूपे क्रेडिट कार्ड को कामयाबी के साथ लिंक करने वाला पहला डिजिटल पेमेंट ऐप बन गया है। इसके अलावा, फोनपे ने यूपीआई पर रूपे क्रेडिट के जरिए, 150 करोड़रुपये की टोटल पेमेंट बैल्यू की भी प्रक्रिया की है। फोनपे का मकसद, यूपीआई पर रूपे क्रेडिट के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि ग्राहक और व्यापारी, दोनों ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल कर सकें। फोनपे पहले से ही देश में 1.2 करोड़मचेंटे आउटलेट्स पर, यूपीआई पर रूपे क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की सुविधा मुहैया करा रहा है। इसकी वजह से क्रेडिट कार्ड इकोसिस्टम में, व्यापारियों के बीच फोनपे की गहरी पैठ बन गई है। यूपीआई के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की वजह से, यह पक्का हो गया हैकि ग्राहकों के पास लेन-देन के लिए, अपने रूपे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कहीं भी और कभी भी करने की सुविधा है। फोनपे, फोनपे ऐप पर ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, ताकि ग्राहक लेन-देन के लिए इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। फोनपे उपभोक्ताओं को ऐसी सूचनाएं भी लगातार भेजता है जिससे सुविधाओं की जानकारी आसानी से समझ में आ जाए। इससे, फोनपे के इस्तेमाल को बढ़ावा मिल रहा है और ग्राहक, यूपीआई की मदद से रूपे क्रेडिट कार्ड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पा रहे हैं।

की पढ़ाई में सहायक तो हो सकते है लेकिन वे कभी भी स्कूल का विकल्प नहीं हो सकते है। इसको आप इसी बात से आसानी से समझ सकते है कि प्रत्येक स्कूल में फ़िजिक्स ,केमेस्ट्री, बायोलॉजी, मेथ्स, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्थित लेब होती है जिससे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल कर विज्ञान के आधारभूत नियम समझ सके, नई एजुकेशन पॉलिसी में भी सीबीएसई का इसी पर जोर है कि स्टूडेंट्स की समझ बेहतर होनी चाहिये। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है ? किसी भी कोचिंग संस्थान में प्रैक्टिकल के लिए कोई लैब होती है क्या? दरअसल पूरी तरह कर्मशियल हो चुके इन कोचिंग संस्थानों में सिर्फ सरकार का ध्यान उनके द्वारा दिए जाने वाले इनकम के साथ तक ही सीमित है , शिक्षा विभाग का इन पर न तो कोई नियंत्रण है और न ही कोई नियम कायदे इन पर लागू होते है। इन कोचिंग संस्थानों के सामने सिर्फ एक चुनौती होती है कि कैसे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में बेहतर नतीजे दे जिससे उनका व्यापार और तेजी से बढ़े। इन कोचिंग संस्थानों से कुछ बच्चे परिणाम देकर बड़े शैक्षणिक संस्थानों में चर्चनित भी हो जाते है लेकिन जीवन की दौड़ में पिछड़ने लगते है। अवसर किसी उच्च शैक्षणिक संस्थान से किसी स्टूडेंट के करीबी के पैकेज पर चर्चनित होने की खबरे तो अखबारों की सुर्खियां बनती है लेकिन बाद में एक -दो साल बाद उनका क्या दृश्न होता है यह सामने कम ही आ पाता है। बड़ी उपलब्धियों के बावजूद कई डिप्रेशन का शिकार होने लगते है। दरअसल इसकी हालत उन्ही कच्चे आम की तरह ही होती है जिन्हें कृत्रिम तरीके से पका दिया गया, बिना यथार्थ के जीवन संघर्ष की गर्मी और अनुभव पाये ये बाज़ार में तो आ गए लेकिन बेस्वाद है !



श्री साई फिजिक्स क्लासेस

Since 32 Year Top Most Physics Class

1st ज.प्र. में आठवां

अनुज माहोरे
इंग्लिश मीडियम
96% फिजिक्स - 98

1st जिलों में प्रथम

सुश्री बरामबले
हिंदी मीडियम
95.4% फिजिक्स - 95

1st जिलों में द्वितीय

रीषभ मालवी
हिंदी मीडियम
94.4% फिजिक्स - 91

कक्षा 12वीं 2023 का सर्वोच्च परीक्षा परिणाम

महागौरी मंदिर के सामने, राजपाल चौक, छिंदवाड़ा, मो. 8989970000

अदि अवस्था
हिंदी मीडियम
93.6% फिजिक्स - 95

तनिष्का माहोरे
इंग्लिश मीडियम
92.8% फिजिक्स - 90

अरध्या कुलकर्णी
इंग्लिश मीडियम
91.6% फिजिक्स - 91

भिरगवी सावंत
इंग्लिश मीडियम
91.4% फिजिक्स - 94

लक्ष्मी मिश्रा
इंग्लिश मीडियम
90.6% फिजिक्स - 91

1st

पूजा सिंघ
हिंदी मीडियम
फिजिक्स - 90

सुरुची बोरा
इंग्लिश मीडियम
फिजिक्स - 94

अंशुल खटके
इंग्लिश मीडियम
फिजिक्स - 90

जीती सिंघ
इंग्लिश मीडियम (एबी)
92.8%

9,10,11,12 वीं के साथ JEE/NEET/CLAT/NDA/PAT/B.Sc. Nur.

विशेष बैचेस प्रारंभ - 1 जून, 5 जून, 15 जून एवं 1 जुलाई